

‘ भगवा आतंकवाद ’ शब्द को गढ़ने वाले अब क्षमा मांगें

जब भगवा आतंकवाद जैसा शब्द जबरन गढ़ दिया गया था तब मैंने मेरी “कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा” पुस्तक में लिखा था कि “भगवा आतंकवाद” जैसा कोई शब्द या टर्म हो ही नहीं सकता, यह एक “अशब्द” है जिसे हमें बोलचाल, लेखन व विमर्श से निकला फेंकना होगा। इस शब्द को मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग, केंद्र में एकाधिक विभागों के मंत्री रहे पी. चिदंबरम, तत्कालीन गृहमंत्री सुशील शिंदे और कांग्रेस ने केवल मोहरा बनकर गढ़ा था। इस शब्द के पीछे वस्तुतः तो वामपंथी छुपे हुए हैं जो प्रेत बनकर वेताल यानि कांग्रेस की पीठ पर अब भी सवार हैं।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में जब भोपाल से साध्वी प्रज्ञा जी के विरुद्ध दिग्विजय सिंह चुनाव में उतरे थे तब उन्होंने समूचे चुनाव को ‘भगवा आतंकवाद’ को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव के मध्य समाचार पत्रों में मेरा एक आलेख भी प्रकाशित हुआ था, जिसका शीर्षक था - ‘भगवा आतंकवाद शब्द की अंत्येष्टि का सटीक समय’। इस चुनाव में जनता ने दिग्विजय सिंह को ‘भगवा आतंकवाद’ जैसा शब्द गढ़ने का यथोचित दंड दे दिया था। इस चुनाव में कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी भी भोपाल के सुंदर तालाब के किनारे पर बैठकर हिंदुत्व को मछली समझकर जाल डालकर बैठे हुए दिखे थे। उन्होंने भोपाल के ताल में एक नया शाब्दिक विष उंडेला था - “हिंदू तो सदा से हिंसक रहा हैं”। अरे, दिग्विजय जी, येचुरी जी, सहित भगवा आतंकवाद शब्द के दोनों पुत्रों को जीवित दीवार में चुनकर मार डालने जैसी दुर्दांत घटना न हुई होती और न ही, मोहम्मद गजनवी श्रीकृष्ण जन्म स्थान को मथुरा में ध्वस्त कर कब्जा पाता। मालेगांव मामले में आए हुए निर्णय का मर्म यही है कि “यदि हिंदू सहिष्णुता और उस पर हुए अत्याचारों का इतिहास और पढ़ना हो तो वे संत मतिदास को पढ़ लें, गुरु तेगबहादुर को पढ़ लें, जलियांवाला बाग पढ़ लें, भगतसिंह के बम फेंकने की मनाबिज शैली पढ़ लें, भारत का धर्म आधारित विभाजन और उसके बाद यहां की भूमि पर मुस्लिमों की बसाहट व पाकिस्तान से हिन्दुओं का मारकाट भरा निर्वासन पढ़ लें, वे सोहरावरदी पढ़ लें, मोपला काण्ड पढ़ लें। और यदि पुराना इतिहास न पढ़ना हो ‘भगवा आतंकवाद’ की माला जपने वाले नेताओं को हाल ही का ‘रामसेतु विध्वंस’ ‘भगवान राम को काल्पनिक कहने का शपथपत्र’ और ‘ऐन दीवाली की रात्रि पूज्य शंकराचार्य जी की गिरफ्तारी का तालिबानी आदेश’ पढ़ लेना चाहिए। इन घटनाओं सहित लाखों अन्य इतिहास सिद्ध घटनाओं ने यह ब्रह्मसत्य स्थापित किया है कि हिंदू हिंसक नहीं सहिष्णु रहा है, क्षमाशील रहा है, सर्वसमावेश को, सर्वस्पर्श को आतुर व उत्सुक समाज रहा है !

मालेगांव के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं द्वारा यह भी कहा गया था कि “आतंकवादी घटनाओं में मुस्लिमों से अधिक हिंदू सम्मिलित रहते हैं”। 2008 के बाद, विशेषकर 26/11 के मुंबई हमले से ठीक पहले, मालेगांव केस को आधार बनाकर कम्युनिस्ट रिमोटेट कांंग्रेसिस्टों ने एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया था कि भारत में आतंकवाद को हिंदू संगठन बढ़ा रहे हैं। लेकिन यह एक वैचारिक आगजनी वाला झुठ था — राजनीतिक लाभ के लिए रचा गया नैरेटिव, जिसकी कीमत निर्दोष हिंदुत्व के मासूम संतों, सैनिकों व नागरिकों ने चुकाई है। लेफ्ट-लिबरल मीडिया, कुछ स्वघोषित बुद्धिजीवी और वामपंथी इतिहासकारों ने इस नैरेटिव को खुलकर समर्थन दिया। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद जैसे लोग, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े थे, उन्हें ‘आतंकवादी’ की तरह पेश किया गया, मीडिया ट्रायल चला, और तथाकथित सेकुलर ताकतों ने उनकी छवि को नष्ट-भ्रष्ट करने के प्रयास किए। साध्वी प्रज्ञा जी ठाकुर को गंभीर स्थिति के कैसर की स्थिति में भी कारावास में रखा गया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई। क्या इस पीड़ा के लिए कोई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? क्या झुठे मुकदमों के लिए जांच एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी? अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो वे चुप हैं— कोई आत्मचिंतन नहीं, कोई क्षमा नहीं। यह उनकी नैतिकता की हार है और इस देश के विवेक के लिए एक चेतावनी भी। आज की आवश्यकता है कि वे हिंदू समाज से उनके द्वारा गढ़े गए छत्र शब्दों के लिए क्षमा मांगे और उनका उत्तरदायित्व हमारा समाज तय करे। कांग्रेस नेतृत्व को अपने इस झुठे नैरेटिव गढ़ने के दोष हेतु देश से क्षमा माँगनी चाहिए।

अजब-गजब

25 साल की लड़की को 76 साल के बुजुर्ग से हुआ इश्क, बोली– घरवाले नाराज, पर शादी करूंगी तो उसी से



‘लव इज़ ब्लाईंड’ कहावत तो आपने सुनी ही होगीपर इस बार तो इसने उम्र की सारी हदों को ही पार कर दिया है। अमेरिका के सेन डिएगो की 25 वर्षीय डायना मोंटानो (Diana Montano) ने प्यार की नई परिभाषा लिखी है, उसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। डायना खुद से 51 साल बड़े यानी अपनी दादा की उम्र के 76 वर्षीय एडगर (Edgar) को दिल दे बैठी है। इतना ही नहीं, घरवाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन डायना का कहना है कि वह शादी करेगी तो सिर्फ एडगर से। क्योंकि, उम्र सिर्फ एक संख्या है। लिए अब जानते हैं कि ये बेमेल जोड़ी आखिर बनी कैसे?

डायना को प्यार की कोई तलाश नहीं थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एडगर की एक्स गल्ट्रीड के जरिए दोनों पहली बार मिले थे, लेकिन डायना ने यह कभी नहीं सोचा था कि वह एडगर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में पड़ जाएगी।

लेकिन कहते हैं न कि वक्त का पहिया कब घूम जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जुलाई 2023 में जब डायना 23 साल की थीं, तब एडगर ने उनसे फोन नंबर मांगा। पहले तो वह एंजोप की वजह से झिझकीं, फिर अपना नंबर दे दिया। डायना बताती हैं कि एडगर पहली ही मुलाकात में उन पर लट्टु हो गए थे। हालांकि, कुछ ही महीनों की बातचीत के बाद एडगर के लिए उनकी फीलिंग्स भी जाग गईं।

द सन में छपी रिपोर्ट के अनुसार, करीब एक साल की लुक-छुप डेटिंग के बाद दोनों हवाई की रोमांटिक सैर पर निकल पड़े। एडगर ने वहीं डायना से अपने दिल की बात कही। उन्होंने कहा, क़ाश मैं जवान होता तो तुमसे शादी कर लेता। इस पर डायना ने भी तपाक से जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। फिर क्या था, वह एडगर की गल्ट्रीड बन गईं।

लेकिन पेशे से नर्स डायना के घरवाले उनके इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। परिवार का मानना है कि वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। डायना ने बताया कि सिर्फ उनकी मौसी ने उनका साथ दिया। उनका कहना है कि वह समझदार ब्यस्क हैं, और अपने फैसले खुद ले सकती हैं। उन्होंने कहा, भले ही घरवाले नाराज हैं, पर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एडगर से। उन्होंने अपने रिलेशनशिप को बेहद जोशीला, खुशियों से भरा और स्थिर बताया है। जैसे ही यह अनोखी लव स्टोरी सोशल मीडिया पर आई, नेटिजन्स के बीच बरस छिड़ गई। लोग इस रिश्ते को ‘घिनौना’, ‘अस्वाभाविक’ और ना जाने क्या-क्या कह रहे हैं। एक यूजर ने तो यह तक कह दिया कि काश तुम पैदा ही नहीं हुई होतीं।

मालेगांव विस्फोट एवं भगवा पर कलंक की साजिश

ललित गर्ग

29 सितंबर 2008 को मालेगांव में हुए बम विस्फोट की न्यायिक परिणति ने एक बार फिर यह सिद्ध किया है कि कैसे सत्ता, वोटबैंक और वैचारिक पूर्वाग्रहों ने भारतीय न्याय और निष्पक्षता की नींव को झकझोर दिया। मुंबई की एनआईए कोर्ट द्वारा सातों आरोपियों-प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित को सबूतों के अभाव में बरी कर देना न केवल कानूनी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण फैसला है, बल्कि यह उस “भगवा आतंकवाद” की मिथ्या कथा पर भी करार प्रहार है जिसे वर्षों तक कांग्रेस ने राजनीतिक मंजों और मीडिया के जरिए प्रचारित किया गया। यह कांग्रेस की फर्जी कहानी का अंत एवं सत्य की जीत का एक अमूल्य आलेख है। अदालत का यह वक्तव्य कि ‘आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म हिंसा का समर्थन नहीं कर सकता’, भारतीय संस्कृति और न्यायशास्त्र की मूल आत्मा को पुनः जीवित करता है। यह वही भारत है जहां ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ और ‘अहिंसा परमो धर्मः’ की गूँथ होती रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश 2008 के बाद हिंदू धर्म, हिंदुत्व और भगवा पर ऐसा कलंक मढ़ा गया मानो वे आतंकवाद के स्रोत हों। मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत उस नतीजे पर पहुंची, जिस पर बांवे हाई कोर्ट देन विस्फोट कांड की सुनवाई करते हुए पहुंचा था। ऐसा कई आतंकी घटनाओं के मामलों में हो चुका है। इससे यही पता चलता है कि कभी जांच एजेंसियां, कभी अदालतें और कभी दोनों अपना काम सही तरह और समय पर नहीं करतीं। जांच और फिर अदालतों कार्यवाही में देरी तथा ढिलाई एक बड़ा रोग है। आतंक के मामलों की जांच में यह भी कोई दबी-छिपी बात नहीं कि संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ, मुस्लिम तुष्टिकरण एवं वोट बैंक बाधा बनते हैं। आतंकी घटनाओं को राजनीतिक रंग दिया जाता है। मालेगांव विस्फोट कांड में प्रज्ञा ठाकुर, सुधाकर द्विवेदी आदि की गिरफ्तारी के आधार पर हिंदू और भगवा आतंक का जुमला उछाला गया। इसका मकसद कथित भगवा आतंक को जिहादी आतंक जैसा बानाना था। यह हिंदू ही नहीं, देश विरोधी साजिश थी। इसका लाभ पाकिस्तान को मिला, क्योंकि कांग्रेस के लोड नेताओं ने समझौता एक्स्प्रेस कांड पर भी एजेंसियों के सहारे भगवा आतंक की फर्जी कहानी गढ़ी। भगवा आतंकवाद शब्द का पहली बार प्रयोग उस समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया, जिनका उद्देश्य स्पष्ट था, वोटबैंक की तुष्टिकरण नीति, मुस्लिम समाज को डराकर एकतरफा ध्रुवीकरण और हिंदू संगठन व सनातन

ब्लॉग

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ रचे गए कांग्रेसी षड्यंत्रों से उपजते सवाल

कमलेश पांडे

मालेगांव बम विस्फोट कांड (2008) के बारे में हाल ही में जो महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, वो किसी भी सजग भारतीय का दिल दहलाने वाले हैं। साथ ही भारत के एक प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस के सार्वजनिक चरित्र के बारे में जो खुलासे हुए हैं, वह उस पर एक गम्भीर लॉछन के रूप भी दिखाई दे रहे हैं। यह भारत के उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों की मनोदशा पर भी प्रकाश डाल रहे हैं, जिन्हें राजनीतिक नाफरमानी की स्थिति में भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमारी संसद को चाहिए कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रत्यक्षित स्थिति से निपटने के लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए कानून बनाए और उनके पाकसाफ हाथ को मजबूत करे। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस के जड़विहीन व खुराफाती रणनीतिकारों यथा- तत्कालीन गृह मंत्री पी.चिदम्बरम, महाराष्ट्र के पार्टी नेता सुशील कुमार शिंदे और तत्कालीन गृह सचिव आर के सिंह आदि ने यूपीए संयोजिका और कांग्रेस सुप्रीमो श्रीमती सोनिया गांधी, जो इंग्लियन ईसाई मूल की भारतीय भारतीय बहू हैं, को प्रसन्न करने के लिए जिस हिन्दू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद की अवधारणा दी और इसी बढाने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करवाने की जो घृणित चाल चली, वही 5 साल बाद कांग्रेसी सत्ता की ताबूत के लिए अंतिम कील साबित हुई। लिहाजा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ रचे गए कांग्रेसी षड्यंत्रों से कुछ महत्वपूर्ण सवाल उपजते हैं, जिसका समुचित जवाब तलाशी जाने की जरूरत है। वहीं, यदि इस मामले के षडयंत्रकारियों को न्याय के कठमड़े में लाया जा सका, तो यह बहुत बड़ी बात होगी। वहीं, राजनीतिक परिदृश्य इस बात की चुगली करता है कि मालेगांव बम विस्फोट कांड की भटकई गई जांच के बाद से कांग्रेस कभी केंद्रीय सत्ता में नहीं लौट पाई। साल 2014, 2019 और 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले पहले यूपीए और अब इंडिया गठबंधन को भारतीय हिन्दुओं ने लगभग खारिज कर दिया। समझा जाता है कि तब सुरसा मुख की भीति फैलते जा रहे इस्त्लामिक आतंकवादर से देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिये कांग्रेसी की बची हुई सियासी साख़्थ की मिट्टी में मिल सकती है। दरअसल, इस विस्फोट की जांच करने वाली एटीएस टीम का हिस्सा रहे पुलिस इंस्पेक्टर महबूब मुजावर ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में जांच के दौरान

अधिकारियों पर दबाव डाला होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस मामले की गोपनीय जानकारी की थी। उन्होंने कहा, ‘मैं अपनी सेवा कर रहा था। मुझे पता था कि ये बातें झूठी हैं, इसलिए मेरे खिलाफ मामले दर्ज किए गए।’ गौरतलब है कि राजनीतिक नाफरमानों की वजह से मनगढ़ंत आरोप लगाकर श्री मुजावर को तत्कालीन राज्य सरकार ने निर्लंबित कर दिया था।

इधर, उनकी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ठीक ही कहा है कि, ‘2008 की मालेगांव साजिश का पर्दाफाश हो गया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़े थे। ऐसे समय में जब इस्लामी आतंकवाद पर बात हो रही थी, सरकार द्वारा उसके वोट देने वालों को नाराज नहीं किया जा सकता था, यही वजह है कि हिंदू आतंकवाद का सिद्धांत गढ़ा गया।’ यह गम्भीर सरकारी पहल थी, जिसकी कांग्रेस ने भारी सियासी कीमत भी चुकाई। इस नए खुलासे के नकारात्मक असर भी बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के बाहर कथित तौर पर विस्फोटक मिलने के बाद, मुंबई पुलिस आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कदाचार के आरोपों के बीच, श्री सिंह को दिसंबर 2021 में निर्लंबित कर दिया गया था। इसके बाद, उन्होंने महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जबरन वसूली और हस्तक्षेप का आरोप लगाया। श्री देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन श्री सिंह पर राज्य सरकार ने जबरन वसूली और इसी तरह के आरोपों में मामला दर्ज किया। ये आईपीएस अधिकारी 2022 में सेवानिवृत्त हुए। हालांकि, एक साल बाद, एकनाथ शिंदे सरकार ने भाजपा को चिढ़ाने के लिए। उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए। इससे भाजपा मनमसोस कर रह गई। जैसा कि एनआईए ने बताया, मालेगांव में विस्फोट रमजान के पवित्र महीने में, नवरात्रि से ठीक पहले हुआ था। एनआईए ने दावा किया है कि आरोपियों का इरादा मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में दहशत फैलाना था। 2018 में शुरू हुआ यह मुकदमा इसी साल 19 अप्रैल को पूरा हुआ। अभियोजन पत्रों से 323 गवाह पेश किए, जिनमें से 37 अपने बयानों से मुकर गए। लिहाजा, विशेष अदालत ने मुजावर को कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह तो साबित कर दिया कि बम विस्फोट हुआ था, लेकिन वह यह साबित करने में विफल रहा कि विस्फोटक मोटरसाइकिल पर लगाया गया था। इसलिए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।

लिहाजा, इस मामले में कुछ सुलगाते सवाल उठना लाजिमी हैं। पहला यह कि कहीं भगवा आतंकवाद के षड्यंत्रकारियों ने ही तो इस बम

बनाया गया, ना फिंगरप्रिंट लिए गए, ना बम के सटीक स्रोत की पुष्टि हुई और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण था। अभियोजन पक्ष ने जिस मोटरसाइकिल को बम के लिए इस्तेमाल होने की बात कही थी, वह भी प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ी नहीं पाई गई। यह सब कुछ बताता है कि पूरा केस पूर्वाग्रहों, दुर्भावना और राजनीतिक साजिश से प्रेरित था। यदि न्याय के नाम पर निपटारे लोगों को प्रताड़ित किया जाए, तो वह केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि समस्त समाज और संस्कृति को दौंडित करने जैसा होता है। प्रश्न यह उठता है-तो क्या अब तक इन आरोपियों को गलत तरीके से आतंकवादी घोषित कर वर्षों तक सलाखों के पीछे रखा गया?

हिंदू धर्म और आतंकवाद-ये दो शब्द आपस में मेल नहीं खाते। सनातन संस्कृति का मूल आधार ही शांति, सहिष्णुता और करुणा है। विरव में यदि कोई भ्रम ऐसा है जिसने ‘युद्ध नहीं, यज्ञ’, ‘हिंसा नहीं, अहिंसा’ का मार्ग दिखाया है, तो वह हिंदू धर्म है। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, विवेकानंद और गांधी-इन सभी की परंपरा में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। ‘भगवा आतंकवाद’ एक गढ़ा गया मिथक था, जो ना केवल हिंदू समाज को कलंकित करता है, बल्कि भारत की आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। भगवा वस्त्रतो त्याग, तपस्या और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। उसे बम और खून से जोड़ना स्वयं भारतीयता के खिलाफ साजिश है। इस फैसले ने जहां एक ओर निर्दोषों को न्याय दिया, वहीं दूसरी ओर यह देश के जन्मानस को आत्ममंथन का अवसर भी देता है, क्या हम इतनी आसानी से किसी को भी आतंकवादी घोषित कर देंगे? क्या हम किसी राजनीतिक विचारधारा के विरोध के कारण पूरे धर्म को कटघरे में खड़ा कर देंगे? क्या धर्म का दुरुपयोग कर वोटेवैंक को राजनीति करते रहेंगे? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की प्रतिक्रिया-‘अज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है’ इस बयान में उनके दर्द एवं यथार्थ की समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक साध्वी की व्यक्तिगत मुक्ति की खुशी नहीं, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आवाज है जिनके लिए भगवा आस्था और अस्मिता का प्रतीक है। वर्षों तक मीडिया ने इस मामले को सनसनीखेज बनाकर ‘हिंदू आतंकवाद’ को ग्लैमराइज किया। फ्राइम टाइम पर भगवा को हिंसा से जोड़ना, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ‘संदिग्ध आतंकी’ की तरह चित्रित करना और बिना न्यायिक पुष्टि के चरित्रनहन करना, फर्कारिता के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ था। वहीं, तथाकथित बुद्धिजीवियों एवं देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी ने भी इस मामले में एकतरफा विचारधारा के चलते भगवा को ‘खतरा’ घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।



रक्षाबंधन से पहले करोड़ों लोगों को मिली राहत, सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर



नई दिल्ली, एजेंसी। सरकारी तेल कंपनियों ने अगस्त महीने के पहले दिन लोगों को बड़ी राहत दी है। हर बार की तरह इस बार भी कंपनियों ने पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर को दामों को अपडेट किया है। ऑयल कंपनियों ने आज शुक्रवार सुबह गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। यह कटौती 19 किग्रा। वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर लागू की गई है।

जानकारी के मुताबिक कंपनियों ने करीब 33 रुपये 50 पैसे की कमी की है। नए दाम आज शुक्रवार 1 अगस्त 2025 से लागू हो गए हैं। वहीं, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जस

के तस बने हुए है। उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बता दें, 14 किग्रा। वाले घरेलू गैस के दामों में आखिरी बार 8 अप्रैल को बदलाव हुए थे। उसके बाद दाम स्थिर बने हुए हैं।

ईंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में कमर्शियल गैस के नए दाम 163150 रुपये हो गए हैं। पहले इसके दाम 1665 रुपये था। मायानगरी मुंबई में यही सिलेंडर अब 158250 रुपये में उपलब्ध होगा। पहले इसकी कीमत करीब 1616 रुपये थी। कोलकाता की बात करें तो इसकी कीमत घटकर 1734।50 रुपये हो गई है। पहले यह

1769 रुपये में बिक रहा था। चेन्नई में कमर्शियल गैस का यही सिलेंडर 1789 रुपये में बेचा जाएगा। पहले यह 1823।50 रुपये में बिक रहा था। बता दें, दाम घटने से होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और फूड ईंडस्ट्री से जुड़े लोगों को फायदा होगा।

बात घरेलू गैस सिलेंडर की करें तो इसके दामों में किसी भी प्रकार की फेरबदल नहीं की गई है। राजधानी दिल्ली में यह 853 रुपये में उपलब्ध है। मुंबई में इसके दाम 852.50 रुपये, हैदराबाद में 905 रुपये, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 890।50 रुपये, बिहार की राजधानी पटना में 942.50 रुपये हैं।

ऐपल ने दर्ज की 2021 के बाद सबसे बड़ी राजस्व वृद्धि

नईदिल्ली, 01 अगस्त। ऐपल ने दिनांक 2021 के बाद अब तक की सबसे बड़ी राजस्व वृद्धि दर्ज की है। तीसरी तिमाही में आईफोन की बिक्री में 13 प्रतिशत की सालाना वृद्धत हुई और कुल राजस्व 10 प्रतिशत बढ़कर 94.04 अरब डॉलर (लगभग 8,200 अरब रुपये) पहुंच गया। विश्लेषकों को इससे कम नतीजों की उम्मीद थी। सीईओ टिम कुक ने कहा कि यह हर लिहाज से एक शानदार तिमाही रही। आईफोन 16 की मांग ने कंपनी के मुनाफे को काफी बढ़ाया है। ऐपल के सेवा कारोबार में 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 27.42 अरब डॉलर (लगभग 2,400 अरब रुपये) तक पहुंच गया। आईक्लाउड और ऐप स्टोर से कंपनी को अच्छी आमदनी हुई। मैक की बिक्री में भी 15 प्रतिशत की वृद्धत देखी गई, जिसमें अपडेटेड मैकबुक एयर की भूमिका प्रमुख रही। यह ऐपल की किसी एक इकाई की सबसे तेज वृद्धत थी। कंपनी ने सकल मार्जिन 46.5 प्रतिशत दर्ज किया, जो अपेक्षा से बेहतर रहा। आईपैड की बिक्री में 8 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 6.58 अरब डॉलर (लगभग 600 अरब रुपये) रह गई। वियरबल्स इकाई, जिसमें ऐपल वॉच और एयरपॉड्स शामिल हैं, का राजस्व 8.64 प्रतिशत गिरकर 7.4 अरब डॉलर पर आ गया। दूसरी ओर, ऐपल को चीन से राहत मिली जहां बिक्री 4 प्रतिशत बढ़कर 15.37 अरब डॉलर तक पहुंची।

रूस-अमेरिका का तनाव हथियारों की तैनाती तक पहुंचा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दो परमाणु पनडुब्बियों को रूस के नजदीकी क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। इसकी वजह है रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के वो बयान, जो अमेरिका को परमाणु हमले की अप्रत्यक्ष चेतावनी जैसे लग रहे हैं। ट्रंप ने इसे फाइनल अल्टीमेटम तक कह दिया।

इसी बयानबाजी के बीच आज से 63 साल पहले यानी 1962 के अक्टूबर की उस घटना की चर्चा हो रही है जिसे क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। ये वो समय था जब अमेरिका और सोवियत संघ एक वास्तविक परमाणु युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए थे।

1- क्या था क्यूबा मिसाइल संकट?

इसे समझने के लिए पहले एक

साल पीछे जाना होगा, यानी 1961 में। ये वो साल था जब बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी। इससे यूरोप में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। दूसरी तरफ वियतनाम में अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा था ताकि दक्षिण वियतनाम को कम्युनिस्ट उत्तर से बचा सके।

इसी समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष होड़ भी तेज थी। रूस ने 1959 में यूरी गगारिन को अंतरिक्ष में भेजकर अमेरिका को चौंका दिया था। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ। केनेडी पर दबाव था कि वो कम्युनिस्ट ताकतों के सामने मजबूती से खड़े हो।

2- सोवियत संघ और क्यूबा की डील

अमेरिका की तरफ से क्यूबा में 1961 की Bay of Pigs नाम की असफल साजिश के बाद सोवियत संघ ने क्यूबा को सैन्य सुरक्षा देने का

फैसला किया। जुलाई 1962 में सोवियत नेता निकिता कुरुचेव और क्यूबा के फिदेल कास्त्रो के बीच एक गुप्त समझौता हुआ सोवियत संघ क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात करेगा। मकसद साफ था कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करे, तो रूस क्यूबा की रक्षा कर सके।

3- क्यूबा को सोवियत संघ के बीच हुई डील की कहानी

The Guardian की एक खबर के मुताबिक मई 1962 में जब सोवियत संघ (रूस) ने क्यूबा में परमाणु हथियार तैनात करने का प्रस्ताव रखा, तो क्रांति से निकली क्यूबा सरकार ने तुरंत हामी भर दी। उस समय क्यूबा खुद को अमेरिका से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा था। अपने सशस्त्र बलों को मजबूत कर रहा था और किसी भी हमले को रोकने की रणनीति तैयार कर रहा था।

डेड इकॉनम से तेल तक... काशी से पीएम मोदी ने ट्रंप को इशारों-इशारों में दिया जवाब

वॉशिंगटन, एजेंसी।”भारत और अमेरिका के बीच इन दिनों टैरिफ के कारण घमासान मचा हुआ है। एक तरफ ट्रंप भारत को हर बात में अपनी सलाह दे रहे तो वहीं दूसरी तरफ टैरिफ की धमकी भी देते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की इन धमकियों पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों ही इशारों में अपना और भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है।

काशी में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के सवालों और भारत क्या करेगा क्या नहीं इसको लेकर साफ कर दिया है। उन्होंने ट्रंप के डेड इकॉनमी वाले बयान पर कहा कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। जल्द ही भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, ‘आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई



आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने-अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं। भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है।

रूस से भारत इस समय तेल खरीद रहा है। ट्रंप ने इसको लेकर कहा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये अच्छी बात है। ट्रंप के इस बयान पर पीएम मोदी ने कहा कि हम क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे, ये सब कुछ

राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए होगा। इससे साफ है कि भारत रूस से तेल खरीदना और अन्य हथियार खरीदना जारी रखेगा। इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

अमेरिका भारत को लंबे समय से अपना फाइटर जेट एफ-35 बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत कई बार इस ऑफर को ठुकरा चुका है। टैरिफ ऐलान के बाद भारत ने अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को खरीदने से इनकार कर दिया है।

कारोबार / दुनिया

केवल पेनल्टी ही नहीं बिलेटेड आईटीआर भरने के ये हैं 5 बड़े नुकसान, ये रही डिटेल्स

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई थी जो अब खत्म हो चुकी है । 31 जुलाई तक अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है और अब बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है । दरअसल, बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए जहां आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं । वैसे तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं । लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस के तौर पर पेनल्टी भरनी पड़ती है । इसके अलावा भी कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं, जिसके बारे में तमाम लोगों को जानकारी नहीं है । आइए जानते हैं...

बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के नुकसान

अगर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं, तो आपको लॉस को अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड की परमिशन नहीं मिलती है । वहीं सामान्य स्थिति में आप लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ।

बिलेटेड आईटीआर भरने वालों को डिफॉर्मेट ब्याज का भुगतान नहीं करता है। बता दें कि समय से आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर को रिफंड दिए जाने की तिथि तक राशि पर 0।5 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज मिलता है।

अगर बिलेटेड आईटीआर दाखिल करते समय कोई टैक्स बकाया है, तो उसे दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा। ये 1% प्रतिमाह की दर से लगाया जाता है। दंडात्मक ब्याज, बकाए टैक्स के प्रकार के आधार पर धारा 234A, 234B और 234C के तहत लगाया जाता है।

बिलेटेड रिटर्न भरने के बाद अगर आपका टैक्स रिफंड बनता है तो ये देरी से मिलता है। आईटीआर फाइलिंग में देरी होने से प्रोसेसिंग देरी से होगी और रिफंड देर से आएगा।

बिलेटेड आईटीआर में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का चुनाव



करने का विकल्प नहीं मिलता। ऐसे में आपको न न चाहते हुए भी न्यू टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न दाखिल करना होता है। बता दें कि जो टैक्सपेयर्स डिडक्शन का फायदा लेकर टैक्स की बचत

करना चाहते हैं, वो ओल्ड टैक्स रिजीम को चुनते हैं। लेकिन डेडलाइन निकलने के साथ ये ऑप्शन भी उनके हाथ से निकल जाता है।

पति- पत्नी किसे भरना होगा किराए की इनकम पर टैक्स? ITR भरने से पहले चेक करें डिटेल



इनकम टैक्स डिफॉर्मेट की ओर से रेंटल इनकम पर टैक्स के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। पहली बात को रेंटल इनकम पर टैक्स देना होता

है। लेकिन इसके नियम हैं। अगर कोई पति-पत्नी किसी घर को ओन करते हैं और उस पर उन्हें कुछ फिक्स अमाउंट का किराया मिलता है। तो उन पर टैक्स लगेगा।आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 26 के अनुसार, जब एक जॉइंट प्रॉपर्टी (मकान) मल्टीपल लोगों के साथ में होती है और उनके शेयर्स फिक्स्ड और क्लियर होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम को हर को-ओनर के हिससे के हिसाब से उनके नाम पर टैक्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है।

कर सकते हैं क्लेम

वहीं, हर को-ओनर अपनी शेयर की इनकम को ईंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकता है। वो सेक्शन 24 के अंडर स्टैंडर्ड डिडक्शन या बॉरोड कैपिटल पर इंटेरेस्ट जैसी डिडक्शन भी अलग-अलग क्लेम कर सकते हैं। यह इनकम हर को-ओनर को अपनी ईंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न में शो करनी होती है। मतलब, हर एक अपने शेयर के बेसिस पर टैक्स का हिसाब देता है, जिससे टैक्स कैलकुलेशन में क्लैरिटी और फेयरनेस रहती है। यह रूल एनफोर्सर करता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी की इनकम को ठीक से डिवाइड किया जाए।

इस शख्स की वजह से दुनिया में छिड़ेगा परमाणु युद्ध!

वॉशिंगटन, एजेंसी। रूस और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक नाम अचानक सुर्खियों में आ गया है, दिमित्री मेदवेदेव। रूस के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने हाल ही में ऐसा बयान दे दिया, जिसे अमेरिका ने सीधी परमाणु धमकी मान लिया।

नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के पास दो परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दे डाला। अब दुनिया सहमी हुई है, क्योंकि दोनों परमाणु ताकतें एक-दूसरे को खुली चेतावनी दे रही हैं।

आखिर ये तनाव कैसे बढ़ा

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते हफ्ते चेतावनी दी थी कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्धविरोध के लिए सहमत नहीं होते, तो अमेरिका रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। ट्रंप ने इसे सीजनफायर-या-सैंक्शन



डेडलाइन करार दिया था। इसका जवाब देते हुए मेदवेदेव ने अमेरिका को रूस की कुख्यात परमाणु प्रणाली डेड हैंड की याद दिलाई एक ऐसा सिस्टम जो अगर रूस पर पहला हमला होता है, तो अपने-आप जवाबी परमाणु हमला कर देता है। ट्रंप ने इस बयान को गंभीर खतरा मानते हुए

रूस के पास परमाणु पनडुब्बियां तैनात करने का आदेश दिया। उन्होंने मेदवेदेव को फेल्ड प्रेजिडेंट कहकर चेतावनी दी कि वो “खतरनाक जमीन” पर कदम रख रहे हैं।

कौन हैं दिमित्री मेदवेदेव?

2008 से 2012 तक रूस के

राष्ट्रपति रहे। उस वक़्त व्लादिमीर पुतिन संविधान के कारण राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे, तो उन्होंने मेदवेदेव को सामने रखा। जन्म लेनिनग्राद (अब सेंट पीटर्सबर्ग) में हुआ। पेशे से वकील हैं। 1990 के दशक से ही पुतिन के करीबी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले गैज़प्रॉम के

चेयरमैन, उप प्रधानमंत्री और चीफ ऑफ स्टॉफ जैसे अहम पद संभाले। राष्ट्रपति रहते हुए New START परमाणु संधि और पुलिस सुधार जैसे शान्तिपूर्ण कदम उठाए थे। 2020 तक रूस के प्रधानमंत्री रहे, अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, पर असल ताकत सीमित मानी जाती है।

परमाणु धमकियों का नया पोस्टर बॉय

राष्ट्रपति रहते हुए मेदवेदेव को उदार और प्रगतिशील चेहरा माना जाता था, लेकिन 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद उनका रूप पूरी तरह बदल चुका है।अब वे लगातार पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की अप्रत्यक्ष धमकियां देते हैं, और सुरक्षा मीडिया पर अमेरिकी और यूरोपीय नेताओं को तंज कसते हैं। जानकार मानते हैं कि ये बयानों का सिलसिला पुतिन और रूसी राष्ट्रवादियों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश है।

हर रोज 8 भारतीयों को अमेरिका से भेजा जा रहा वापस, बाइडेन के समय सिर्फ इतना था आंकड़ा

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में कई बातों और फैसलों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे वो अवैध प्रवासियों का मामला हो या फिर दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का मामला हो। हर बार वे किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन ने 1700 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट किया है। ये आंकड़े बाइडन सरकार की तुलना में तीन गुने से भी ज्यादा हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका से भारतीयों के निर्वासन के आंकड़ों में तेजी देखने को मिली है। मौजूदा सरकार और पुरानी सरकार की तुलना की जाए तो ये आंकड़े तीन गुने से भी ज्यादा हैं। छह महीनों के भीतर ही अमेरिका से 1703 लोगों को भारत वापस भेजा गया है।

जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप

के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका से भारतीय नागरिकों के निर्वासन में तेजी देखने को मिल रही है। जो बाइडेन प्रशासन के दौरान देखे गए दैनिक औसत से लगभग तिगुना है। विदेश मंत्रालय (MEA) के आंकड़ों के अनुसार, इस साल केवल साढ़े छह महीनों में 1,703 भारतीयों को निर्वासित किया गया है। लगभग हर दिन आठ, जबकि जनवरी 2020 और दिसंबर 2024 के बीच औसतन तीन प्रतिदिन थे। यह तेजी पिछले साढ़े पांच सालों में दर्ज किए गए सभी भारतीयों के निर्वासन का लगभग एक चौथाई है, जिनकी कुल संख्या 7,244 है।

अमेरिकी विदेश विभाग ने बीजा धारकों को एक चेतावनी जारी की थी। इसमें कहा गया था “हम बीजा धारकों की लगातार जांच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी अमेरिकी कानूनों और आब्रजन नियमों का पालन कर रहे हैं। अगर

वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम उनके बीजा रद्द कर देंगे और उन्हें निर्वासित कर देंगे। पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि अमेरिका ने अपने बीजा नियम और भी सख्त किए हैं।

कब-कब डिपोर्ट किए गए भारतीय?

इस साल में अब तक 1,703 निर्वासनों में से 864 व्यक्तियों को अलग-अलग अमेरिकी एजेंसियों की तरफ से आयोजित चार्टर और सैन्य उड़ानों से वापस भेजा गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने 5, 15 और 16 फ़रवरी को सैन्य उड़ानों के ज़रिए 333 भारतीयों को वापस भेजा था। 19 मार्च, 8 जून और 25 जून को 231 अन्य लोगों को आईसीई चार्टर प्लेन से डिपोर्ट किया गया। गृह सुरक्षा विभाग ने 5 और 18 जुलाई को 300 और भारतीयों को डिपोर्ट किया है।



तेजस्वी का दावा- वोटर लिस्ट से नाम कटा, चुनाव आयोग ने आरोपों को बताया गलत

दोगुनी हुई BLO की सैलरी, बिहार SIR में शामिल इन कर्मचारियों की भी लगी लॉटरी

पटना। RJD नेता तेजस्वी यादव ने SIR के मामले पर फिर आक्रामक रुख दिखाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में धोधली की गई है। शनिवार को एक पोलो रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने यह बातें कहीं। उन्होंने ये भी दावा किया कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी के इस आरोप का चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। उसने वोटर लिस्ट दिखाकर बताया कि तेजस्वी का नाम सूची में मौजूद है।

इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शुरू से ही इस पूरे मामले पर अपनी आवाज को उठाते रहे। हमारे सुझाव को नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की भी अनदेखी चुनाव आयोग की तरफ से की गई। शुरू से ही हमारा कहना था कि जो नई वोटर लिस्ट आएगी तो कई गरीब लोगों के नाम नहीं रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि किसी का नाम नहीं कटेगा।

वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव

तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। उनका



नाम काट दिया गया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? तेजस्वी ने दावा किया है कि उन्होंने एसआईआर के दौरान गणना प्रपत्र भी भरा था, इसके बावजूद भी नाम काटा गया है।

तेजस्वी नेता ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सूची सभी राजनीतिक दलों को दी जा रही है, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका है। वह हम लोग बताएंगे।

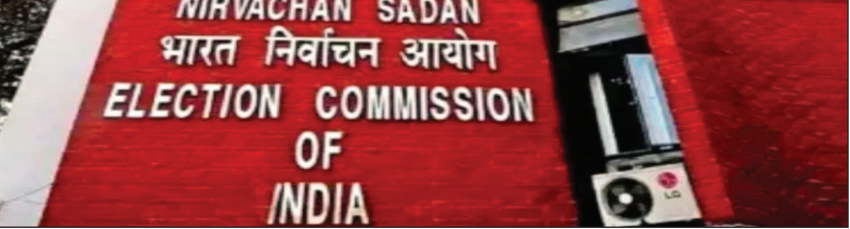
चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए हर नाम की जानकारी और कारण बताया जाएगा। कल हमारा महागठबंधन के डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था। हमने अपनी बातों को रखा है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी हमारी

गए हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने चालाकी और सजिश करते हुए न तो बूथ का नाम दिया है और न ही वोटर का पता दिया है, जबकि चुनाव आयोग को हम चुनौती दे रहे हैं कि वह पूरी जानकारी दे। चुनाव आयोग अपनी तरफ से जो भी जानकारी उपलब्ध कराता था, तो विभिन्न कारणों का हवाला देता था और बताया जाता था कि किन कारणों से नाम कटा है।

तेजस्वी ने कहा कि सबसे अहम ईपीआईसी नंबर नहीं दिया है ताकि हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करें। यह चुनाव आयोग की चालाकी है। आपने पहले से ही मन बना लिया है कि किस पार्टी की सरकार बनानी है, तो इसी सरकार का एक्सटेंशन कर दीजिए। अगर अस्थाई पलायन से 36 लाख मतदाताओं का नाम कटेगा तो भारत सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार बिहार से बाहर तीन करोड़ से भी ज्यादा पलायन है। इस संख्या से ज्यादा होना चाहिए। अगर इलेक्शन कमिशन की माने तो यह संख्या तीन करोड़ से ऊपर होती है। क्या इनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया था? क्योंकि यह गाइडलाइन में लिखा हुआ है। क्या मतदाताओं को उनका नाम काटने से

‘EC ने पहले ही मन बना लिया किस पार्टी की सरकार बनानी है’

उन्होंने कहा कि हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। लगभग 8।50 प्रतिशत नाम काट दिए



पटना। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अपने बूथ लेवल कर्मचारियों (blo) की वेतन बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने कर्मचारियों का वेतनमान दोगुना कर दिया है, जिन कर्मचारियों को 6000 रुपये मिलते थे, अब यह राशि दोगुनी होकर 12000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि कर दी गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से इस संबंध में जानकारी भी उपलब्ध करा दी गई है।

निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने बीएलओ के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना किया है। इसके अलावा मतदाता सूचियों की तैयारी एवं पुनरीक्षण में शामिल बीएलओ पर्यवेक्षकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

आयोग की तरफ से जानकारी दी गई है कि 10 साल पहले 2015 में ऐसा संशोधन किया गया है। साथ ही साथ पहली बार इआओ यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और ईआईआओ यानी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए मानदेय प्रदान किया गया है।

चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ को अब तक केवल 6 हजार रुपये महीने का वेतन दिया जा रहा था। इसमें बदलाव करते हुए बीएलओ की वेतन 12000 रुपये की जाती है। इसके साथ ही जो बीएलओ मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) में लगे हुए हैं उनको 1 हजार रुपये के बदले 2 हजार रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे।

इलेक्शन कमिशन ने बीएलओ पर्यवेक्षक की भी सैलरी बढ़ा दी है। अब तक 12 हजार रुपए मिल रहे थे जिसे संशोधित कर दिया गया है। अब

उन्हें 18000 रुपए मिलेंगे। ईआओ को 25 हजार रुपए जबकि ईआईआओ को 30 हजार रुपए मिलेंगे। इन दोनों को ही अब तक कुछ भी नहीं मिल रहा था।

इलेक्शन कमिशन ने इस बात की भी जानकारी दी है कि बिहार से शुरू होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए बीएलओ हेतु 6000 रुपए के विशेष प्रोत्साहन को मंजूरी दी थी। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची मशीनरी जिसमें निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और बूथ लेवल अधिकारी शामिल है। जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सभी निष्पक्ष और पारदर्शी मतदाता सचिया तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसलिए आयोग ने इन सभी के वार्षिक पारिश्रमिक को दोगुना करने का निर्णय लिया है।

बॉलीवुड हसीनाएं, जिनकी एक्टिंग के दम पर फिल्ममें हुईं सुपरहिट

विदेशी पर्यटक को कूड़ा उठाते देख भड़कीं कंगना रनौत, गंदगी फैलाने वालों को कहा- शर्म करो



महिलाओं ने बॉलीवुड में अपनी काबिलियत को बखूबी दिखाया है। बॉलीवुड की कई ऐसी हीरोइनें हैं, जिन्होंने फिल्म बिना किसी हीरो के अपने बूते हिट करवाई है। कहने का मतलब साफ है कि अगर ऐसा समझा जाए कि सिर्फ हीरो के दम पर ही फिल्में चलती हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर फिल्म में हीरोइन का रोल दमदार हो, तो इसका कमाल दिखना तय है। आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन हीरोइनों की बात करेंगे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से फिल्म को हिट और सुपरहिट की श्रेणी तक पहुंचाया।

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट की बात करें, तो उनकी फिल्में ‘गंगुबाई काठियावाड़ी’ और ‘राजी’ ऐसी फिल्में हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों ही फिल्मों में आलिया का लीड रोल था। आलिया का अभिनय ही था कि ये दोनों फिल्में दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हुईं। ‘गंगुबाई काठियावाड़ी’ के लिए तो आलिया को नेशनल अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया। ‘गंगुबाई काठियावाड़ी’ ने 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया। कम बजट में बनी ‘राजी’ ने भी 100 करोड़ से ज्यादा कमाए।

सोनम कपूर

जब महिलाओं पर आधारित फिल्मों की बात करें, तो ऐसे में



सोनम कपूर का और उनकी फिल्म ‘नीरजा’ का जिक्र जरूरी हो जाता है। सोनम कपूर ने इस फिल्म में अशोक चक्र से सम्मानित नीरजा भनोट का रोल निभाया था। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह एयर होस्टेस ने अपनी जान की बाजी लगाकर विमान में मौजूद यात्रियों को बचाया था। सोनम ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में जान डाली दी थी।

कंगना रणौत

विकास बहल के डायरेक्शन में बनाई गई कंगना रणौत की फिल्म ‘कवीन’ का जादू ऐसा चला कि फिल्म ने खूब तारीफ पाई। कंगना का शानदार अभिनय फिल्म को कामयाब बनाने के पीछे की एक बड़ वजह रहा। इस बेहतरीन फिल्म के बाद तो कंगना को फैस ने बॉलीवुड क्वीन नाम ही दे दिया। रानी मेहरा के किरदार ने दर्शकों के दिलों पर एक अभिमत छाप छोड़ी है।

रानी मुखर्जी

फिल्म ‘मर्दाना’ में रानी मुखर्जी के एक्शन सीन्स का ऐसा जलवा दिखा कि फैस को भा गया। सीन्स के साथ उनका एक-एक डायलॉग ऐसा था जिसे एक बार सुनो, तो लंबे समय तक आपके कानों में गूंज रहेगी। एक डायलॉग आपको भी याद दिलवा दें- ‘जिस दुनिया में मां बहने रिश्ते नहीं गाली हैं, उस दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी।’ रानी का कमाल ही था कि फिल्म को हिट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

विद्या बालन

विद्या बालन की ‘डर्टी पिक्चर’ की बात करें, तो फिल्म में विद्या बालन की एक्टिंग ने ऐसा कमाल किया कि बहुत ही कम बजट में बनने के बावजूद इसने खूब अच्छा प्रदर्शन किया। विद्या ने अपना बोलूड अवतार दिल खोलकर दिखाया। फिल्म का पहला पोस्टर आते ही विद्या की बोलूड इमेज की चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही विद्या ने अपनी जोरदार एक्टिंग से सबको हैरान कर दिया।



बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक विदेशी पर्यटक को कूड़ा उठाते हुए देखा जा सकता है। इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने प्रतिक्रिया भी दी है। आइए जानते हैं क्या बोलीं एक्ट्रेस।

क्या है वायरल वीडियो?

हाल ही में एक्ट्रेस-पॉलिटािशियन कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया है, जिसमें एक व्यक्ति झरने के पास से कूड़ा उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ भारतीय पर्यटक उस नजारे का आनंद लेते या इधर-उधर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कूड़ा उठाने के बाद, उस व्यक्ति ने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, ‘अगर मेरे पास एक दिन खाली हो, तो शायद मैं यहां बैठकर देखूं और लोगों से कहूं- इसे उठाओ। मैं ऐसा करूंगा। मुझे किसी को बताने में कोई दिक्कत नहीं है।’ ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा

है।

कंगना रनौत ने कहा- शर्मनाक

इस वायरल वीडियो क्लिप को अपने इंस्टा स्टोरी पर शेयर करते हुए कंगना रनौत ने लिखा कि शर्मनाक। आपको बताते चलें कि इस वीडियो को हिमाचल प्रदेश का ही बताया जा रहा है। इस वजह से एक्ट्रेस ने अपने राज्य की जनता को इसके माध्यम से संदेश दिया है कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें।

कंगना रनौत का वर्कफ्रंट

अभिनेत्री कंगना रनौत के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें आखिरी बार ‘इमरजेंसी’ फिल्म में देखा गया था, जिसमें वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आई थीं। इसके अलावा अभिनेत्री की आगामी फिल्मों की बात करें तो वह आर माधवन के साथ अगली फिल्म में नजर आने वाली हैं, जिसका नाम है ‘सर्कल’।

